Future of Goa

\+

*333. Shri D. C. Sharma:
Shri Yashpal Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri R. S. Pandey:
Shri Bade:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Bagri:
Shri Basappa:
Shri Raghunath Singh:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri R. Barua:
Shri Tan Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Sivamurthi Swamy:
Shri Jashvant Mehta:
Shri Kanakasabai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken about the future of Goa;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter needs very careful consideration in all its aspects.

Shri D. C. Sharma: Why has it become the policy of the Government of India to keep a question hanging till it reaches the combustible point and then decide about it? How long will it take to take a decision on this question?

Mr. Speaker: The second part may be answered.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): This is being considered now. I think it should not take a very long time now to decide it.

Shri D. C. Sharma: While considering the relative claims of Mysore and Maharashtra, will Government have recourse to a referendum to decide this question or to a general election or to a committee to decide the question?

Shri Nanda: One thing is certain, that the wishes of the people will be consulted. What is going to be the form, I cannot say.

Shri S. M. Banerjee: It is already there.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं मंत्री जी से मालूम कर सकता हूं कि कब तक जनता की राय मालूम कर ली जाएगी । इलेक्शन में तो जनता की राय आ चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय: जनता की विशेज कब तक मालूम कर ली जाएगी ?

श्री नन्दा : मैंने कहा कि जल्दी ही इसका फैसला करने की कोशिश होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गोआ के जो पिछले सामान्य चुनाव हुए थे उसमें गोआ की एक पार्टी ने अपने चुनाव का केवल यही आधार बनाया था कि गोआ को महाराष्ट्र में मिलाना चाहिए, और उस पार्टी ने चुनाव में विजय प्राप्त की और वह पार्टी इस समय वहां पर अपना मंत्रिमंडल बना कर कार्य कर रही है । ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर क्या आवश्यकता हुई सरकार को कि वो उन्होंने दोबारा वहां पर जनमतसंग्रह या और किसी प्रकार का नारा लगाया ? क्या इससे गोआ की आन्तरिक स्थिति ज्यादा विषम नहीं हो जाएगी ?

श्री नन्दा : उसके बाद बहुत सा अर्सा गुजर गया और कई वाकयात हो गए, और उस गवर्नमेंट ने खुद अपनी एक तजवीज पेश की है जो पहले से मुख्तलिफ है ।

Shri R. S. Pandey: In order to determine the future of Goa, has the Chief Minister of Goa made certain suggestions? If so, what are they?

Shri Nanda: This is very well known, that he wants that there should be a fresh reference to the people.

श्री बड़े : जो पिछले चुनाव हुए थे और जिनके फलस्वरूप जो पार्टी इस समय गोआ में शासन चला रही है उसने कहा था कि गोआ को महाराष्ट्र में मिलाना चाहिए । क्या यह बात सही नहीं है कि अब मैसूर का प्रेशर पड़ने से सरकार इस विचार में पड़ गयी है कि इसको मैसूर में मिलाया जाए या महाराष्ट्र में मिलाया जाए ?

श्री नन्दा : इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सारे सवाल पर विचार हो रहा है ।

Shri Basappa: May I know whether the suggestion for mid-term elections is not beset with dangers, and also whether it is not a very hasty and *ex parte* decision, whether it is not a surrender to power tactics of some people? Is it not true that it is not in the interest of Goa or in the interest of India or in the interest of all national elements in the country?

Mr. Speaker: Does he want an answer or he has said what he wanted?

Shri Basappa: I want to know whether there is any objection from the Goan people and the people of Mysore to this, and whether there was any demonstration against this move or decision?

Shri Nanda: There is no decision so far.

Shri P. R. Chakraverti: Has Government taken any decision to refer this question to a plebiscite of the people of Goa?

Shri Nanda: I have already said that the form in which the wishes of the people there should be consulted has not been decided.

श्री मधु लिमये : बंगलोर की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के पहले इस बात का एलान हो चुका था कि गोआ के सम्बन्ध में कुछ फैसला हुआ है । प्रधान मंत्री और गोआ के मुख्य मंत्री के बीच मुलाकात और बातचीत हुई और उसके बाद एक फैसला हुआ और महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी ने उस पर अपनी मुहर भी लगायी थी। उस समय मुख्य मंत्री बान्दोडकर जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि बंगलोर में कांच के घर में जो बैठक हुई और उस पर जो पत्थर फैंके गए क्या उससे डर कर गृह मंत्री कहते हैं कि फैसला नहीं हुआ ? सचमुच में इसके बारे में फैसला हुआ था या नहीं ?

श्री नन्दा : सारी बातों पर चर्चा हुई और इन बातों को सोचा गया, कुछ इरादे बताए गए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया ।

श्री बागड़ी : गोआ का मामला या इस तरह के और प्रान्तों के मामलों को क्या सरकार कोई एक नीति बना कर हमेशा के लिए तै करने का विचार करती है जिससे कि बार बार गड़बड़ी पैदा न हो ? क्या सरकार इस दिशा में कुछ कार्य कर रही है ?

श्री नन्दा : जैसे जैसे सवाल पैदा होते है, वैसे वैसे उनका हल करना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उनका ऐतराज है कि जब कोई इश्यू पैदा होता है तो आप उस को हल करते है, सारी बातों को सामने रख कर कोई हल क्यों नहीं करते ?

श्री मधु लिमये : पत्थर जब गिरने लगते है तब हल करने लगते है, यह बुरी बात है ।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन यह आदत भी अच्छी नहीं है कि जब दूसरे का सवाल हो रहा हो तो आप खड़े हो जाएं ।

श्री नन्दा : उसके बारे में तो फैसला किया गया । मगर जब नए हालात पैदा होते हैं तो उनके बारे में सोचना पड़ता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि गोआ कांग्रेस कमेटी और गोआ असेम्बली का विचार क्या है ?

श्री नन्दा: उनके विचार अलाहिदा अलाहिदा हैं ।

Shri S. N. Chaturvedi: What will be the alternative terms of reference and may I know whether a clear verdict can be obtained on the issue without a plebiscite or referendum,—in a general election?

श्री नन्दा: यह भी एक तरीका है और भी हो सकते हैं । उन सब पर सोचा जाएगा । सब बातों का ध्यान रखा जाएगा ।

Shri M. L. Jadhav: How far is it economically and administratively desirable to keep a small territory like Goa as a separate Union Territory?

Mr. Speaker: That is what they are considering.

श्री तन सिंह: पहले सरकार ने घोषणा की थी कि गोआ के भविष्य पर दस वर्ष तक किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा । सरकार को मालूम है कि वहां एक पार्टी ने इसी प्रश्न के आधार पर चुनाव जीता है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी कि सरकार को इस प्रश्न पर दस वर्ष से पहले ही विचार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई ?

श्री नन्दा: उस वक्त यही कहा गया था कि कुछ अरसे के बाद वहां के लोगों की राय ली जाएगी, उन से पूछा जाएगा । अब सवाल यह है कि उतना अरसा लगाया जाए या जल्दी इस फैसले को किया जाए । इस में कोई सिद्धांत का सवाल नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : गृह मंत्री जी के जवाब से मालूम हुआ कि क्योंकि समय गुजर गया है इसलिए वह फैसला जो कि प्रजातांत्रिक उसूलों पर दिया गया था काफी पुराना हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस चीज की आशा में हैं कि जब तक गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए कोई बहुत बड़ा आन्दोलन न हो तब तक उस पर निर्णय नहीं लेंगे । और क्या यह सही है कि कांग्रेस के आपसी झगड़े के कारण गोआ का भविष्य अंधकार में है ?

श्री नन्दा : फैसला अभी होगा, जल्दी होगा ।

Shri R. Ramanathan Chettiar: In view of the emergency resulting from Chinese aggression and the present Kashmir situation, why not Government keep issues like Goa in cold storage for ten years as suggested by the late Prime Minister.

Mr. Speaker: Suggestion.

Shri Alvares: The Home Minister has repeatedly said that certain conditions have changed since the clear verdict of the last election in favour of merger with Maharashtra. May I ask the Home Minister what the new conditions are?

Shri Nanda: It is a conclusion which the hon. Member draws. We have already said that we are reconsidering the whole situation.

Shri Alvares: He has not answered my question. He said new conditions had developed. What are the new conditions?

Shri Nanda: To infer from that and to draw a certain conclusion from the elections—I do not think that has been an accepted position.

Shri Alvares: He is going to have another election for a verdict. One election has already given a verdict.

What are the conditions which have intervened for having another verdict?

Shri Nanda: I have said that the elections brought about a certain situation. Later on, that Assembly passed a certain resolution. After that, the Chief Minister himself made a certain offer which is on the basis of consultations with others concerned. The matter has been taken up and a decision will be reached soon.

Archaeological Survey of India

*334. **Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the recommendations made by the Review Committee appointed to suggest lines on which the Archaeological Survey of India should work in the next five years have been considered;

(b) if so, the decisions taken thereon;

(c) whether the financial implications of the proposals made have been considered; and

(d) if so, with what result?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (d). The recommendations of the Committee are under consideration.

Shri Shree Narayan Das: May I know how long Government will take now to come to a decision in the matter?

Shri M. C. Chagla: As the hon. Member knows, the report was presented only on the 2nd of April. As a matter of fact, some recommendations have already been implemented. We are awaiting the report of the Director-General. When it comes, it will be considered by the Ministry, and the recommendations which we accept will be implemented without delay.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether it will be possible for the Government to get some of the suggestions made by this committee included in the Fourth Plan?

Shri M. C. Chagla: Yes, we are going to accept most of the recommendations. I do not know how many of them will be included in the Fourth Plan. That is not in my hands.

Shri Ranga: The Minister said just now that it was submitted only in April. Now we are in September. Are not four months enough? The Director-General has not sent his reactions in regard to this report. Is this the speed or rate at which my hon. friend proposes to reorganise his Ministry and bring some sense into this Government? Does it go on like this because it relates to archaeology?

Shri M. C. Chagla: I do not think my hon. friend is fair to me or to the Ministry. I wish he only knows the history of reports, how long they take. There are certain recommendations. He may look at the report, it has been laid on the Table. It takes time for the Director-General to examine it. As I said, some of them have already been implemented.

Shri Ranga: Some of them have been implemented. In regard to the rest of them, he has not even received a reply, and my hon. friend proposes to go on examining it again for another five years, and then his successor will have to do it I suppose.

Shri M. C. Chagla: I did not say five years.

Repatriation of Indians from Burma

\+

*335. **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri P. C. Borooah:
Shri Mohammed Koya:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri Karni Singhji:

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given